

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
हुक्म की तारीख  
में जारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

15/3/22

पत्रावली बास्ते आदेश पेश हुई। पत्रावली में  
उपलब्ध रिपोर्ट, पृष्ठ 212, जवाब का  
अवलोकन किया। बहस उभयपक्षधारण पर  
मनन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर  
विचार करने और बहस सुनने के उपरान्त इस  
न्यायालय द्वारा तीन 'बिन्दुओं' को तय करना  
है।

प्रथम दृष्टया मामला :- शर्मागण द्वारा संवत्  
2060-2063 तथा इसके पहले के पुराने राजस्व  
अभिलेख की प्रतियां पेश की गईं तथा मिलान  
खसरा भी पेश किया हुआ है। वर्तमान अभिलेख की  
नई छाता सं. 182 की आराजी सं. 104 वर्गों  
कुल रकबा 7.26 हेक्टेयर का पुराने अभिलेख  
में आराजी सं. 534/78 वर्गों कुल रकबा 28  
बीघा 15 बिस्वा के रूप में दर्ज होना तथा  
गोपालदान चारण की विरासत से शर्मा सायर  
कुंवर वर्गों की प्राप्त होना भी प्रथम दृष्टया  
जाहिर है। इसी न्यायालय में पूर्व निर्णित वाद  
222/1990 निर्णय 7.09.2000 में उपरोक्त  
आराजियात शामिल है। श्रीमती भूरकुंवर  
भी पक्षधार रही है। बाद के निर्णय के मुताबिक  
उपरोक्त आराजियात की भूमियां शर्मा  
सायर कुंवर की एकाग्र छातेदारी में घोषित  
होना जाहिर है। इस प्रकार वादग्रस्त  
भूमि में शर्मा प्रथम दृष्टया संबंध तथा  
मामला शामिल करने में सफल रही है।  
विपक्षी सं. 01 ने अपना 1/2 हिस्सा जरिये  
विरासत वसीयत प्राप्त होना बताया है किन्तु  
उक्त वसीयत श्रीमती भूरकुंवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहं काम हुक्म की में जार
----------------	------------------------------------	---

यह सभी तथ्य विधिवत् विचारन से मूलवाद  
 में तय होंगे जिन पर इस स्तर पर और  
 निष्कर्ष पारित नहीं किया जा सकता है।  
 इसी न्यायालय से पूर्व में शर्षियां की जवाबदारी  
 का जो अनुतोष दिया है उसे सुरक्षित रखा  
 जाना तथा विपही सं० ०। ३ भी ऐतराज की  
 सू विधिवत् मूल दावे में तय किया जाना  
 उचित पाने से प्रथम दुहटया मामला शर्षियां  
 के पक्ष में बनना पाया जाकर मूल दावे के  
 निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार  
 किया जाना उचित है।

सुविधा का संतुलन :- शर्षियां का तट्टे स्टा  
 डि विवादित भूमियों में जो कुये की भूमि  
 है उस पर वर्तमान में उन्ही का उनेम्शन व  
 मोटर लगी है। विपहीगण को पाबंद नही  
 करने पर उनके एठमात्र हिस्से में हस्तक्षेप  
 होगा तथा झगडे बढेंगे। इससे विपरित  
 विपही सं० ०। ३ और ले कुचन स्टा डि  
 उनके द्वारा डिमांड शर्षि जमा कराया जा  
 चुकी है। और मोटर उनेम्शन नही होने  
 पर फसल लूण जायेगी। शान अल्वीहन  
 है कि अब तक विपही सं० ०। ३ के उचन  
 भूमि पर विद्युत उनेम्शन प्राप्त नही रहा  
 विपही सं० ०। ३ अधिकाता का प्रमुख ऐतराज  
 यह रहा कि विपहीयां सहजवातेदार है  
 और उनके विरुद्ध सयगन स्वीकार नही  
 किया जा सकता। उनके द्वारा निम्न न्यायिक  
 इच्छांत पेश किये गये-

अज  
किस्

नम्बर व  
अहकाम  
हुक्म की  
में जारी

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

मुकाम

बनाम

किस्म मुकद्दमा

नं.

सन्


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त अहकाम जो हुक्म की त में जारी ह
	<p>इसके जवाब में प्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा निम्न दस्तावेज पेश हुये -</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) RRT 2020(2) पेज 1081</li><li>(2) RRT 2020(1) पेज 474</li><li>(3) RRT 2019(1) पेज 271</li></ol> <p>उक्त न्यायिक दस्तावेजों का सलममान अवलोकन किया गया। हस्तगत मामले में जो हुक्म की भूमि है उनके प्रस्तुत फौरोग्राफ से और इसी न्यायालय के निर्णय से प्रार्थिया अपना प्रथम दृष्टया मामला पूर्व स्थापित कर चुकी है। न्यायिक दस्तावेजों में नवीनतम व्यवस्था भी यही है कि जहाँ तीनों ताकिठ बिन्दु प्रमाणित ले सहकार्यकार के विरुद्ध स्थगन प्रदान किया जा सकता है। यदि स्थगन प्रदान नहीं किया गया तो मामले में पेचीदगियां बढ़ेंगी। विवाद बढ़ेंगे और भूमि हस्तांतरित होने की संभावना भी रहेगी जबकि अब तब विपक्षी सं० ०१ को और उनेशान प्राप्त नहीं रहा है। जो वैकल्पिक व्यवस्था होगी।</p>	

अपूर्णनीय क्षति :- पूर्व वर्णित अनुसार चूँकि

दोनों बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में तय ठिये जा चुके हैं। प्रार्थिया संवत् 2032 से यानि 35 वर्ष से अधिक समय ले उक्त भूमि की स्वतैदार है व उपयोग कर रही है और न्यायालय के निर्णय ले एकमात्र जातेदारी घोषित की जा चुकी है जबकि विपक्षियां संवत् 2056 में सहस्वतैदार बनी है। विपक्षिया का यह एतराज कि प्रार्थिया का दावा मियाद बाहर है और बसीयत खारिज ठिये बिना नहीं चल सकता है।

इस बिन्दु पर मूल वाद में तनही बनकर तय होंगे किन्तु इस तरह के आधार पर स्थगन अस्वीकार करना उचित नहीं है क्योंकि जहां मूलवाद में विपक्षियां की स्वतैदारी की चुनौती दी हुई है और मौजूदा विद्युत उन्मेशान ले प्रार्थिया के नाम पर बताया गया है तो स्थगन प्रदान नहीं करने पर प्रार्थिया के एक निर्दिष्ट रूप ले प्रभावित होंगे जिनकी शर्त संभव नहीं है और हस्तान्तरित हो जाने पर दावा पेश होने का प्रयोजन तमर्थ मूल वाद घोषणा का है जो महत्वपूर्ण प्रकृति का है।

तथा दावे में एक अधिकार पक्षकारान के तय होने तक स्थगन तय होने तक स्थगन प्रदान नहीं करने पर अपूर्णनीय क्षति प्रार्थिया के लोमी अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार तीनों बिन्दुओं की तय कर इस न्यायालय की पूर्व में दिनांक 16/8/2021 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश की कन्फर्म कर बाद

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>भाराजी नं. 104, 109, 234, 312, 313, 363, 370, 371, 374, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 390, 393, 397, 399, 403, 406, 407 कुल रकबा 7.26 हेक्टेयर भूमि की राजस्व अभिलेख एवं मौजे की यथावत् स्थिति बनाये रखे और किसी अन्य द्यार्मित की विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया जावे। नग निर्णय सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली मूल वाद लैलगन से।</p> <p style="text-align: right;">             (विन्दु बाला राजावत)            उपखण्ड अधिकारी R.A.S.            बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़         </p>	